

कृषि उत्सव

25 अगस्त 2025



ASCI
Agriculture Skill Council of India

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA



www.ceasi.in



प्रिय पाठकों,
हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के माध्यम से आप तक पहुँच पाना हमारे लिए एक विशेषाधिकार है। यह समाचार पत्र CEASI की गतिविधियों की धड़कन को दर्शाता है, जो ASCI के संरक्षण में कार्यरत है, और हमारे सामूहिक सफ़र को कौशल विकास एवं सतत कृषि की दिशा में प्रतिबिंबित करता है। यहाँ साझा की जाने वाली हर कहानी हमारी टीमों, साझेदारों और कृषि समुदायों की समर्पित भावना का प्रमाण है। हमारा मिशन स्पष्ट है: किसानों और कृषि-पेशेवरों को वह कौशल, ज्ञान और तकनीक प्रदान करना जिसकी उन्हें बदलते समय में सफल होने के लिए आवश्यकता है। नवाचार और जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मिलाकर, हम एक अधिक उत्पादक, लचीले और समावेशी कृषि क्षेत्र की नींव रख रहे हैं।
मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप इस समाचार पत्र को पढ़ें, सीखें और इसमें प्रस्तुत अवसरों में सक्रिय रूप से भाग लें। आपकी सहभागिता ही विचारों को प्रभाव में बदलती है।

डॉ. सतेंद्र सिंह आर्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी



प्रिय पाठकों,
CEASI का साप्ताहिक समाचार पत्र केवल गतिविधियों का सारांश नहीं है। बल्कि यह एक ऐसा मंच है, जहाँ विचारों का आदान-प्रदान, उपलब्धियों का उत्सव और भारतीय कृषि तथा इसके सहायक क्षेत्रों जैसे डेयरी, बागवानी, कृषि मशीनीकरण, जलवायु लचीलापन आदि के भविष्य के लिए हमारी साझा दृष्टि को और मजबूत किया जाता है। प्रत्येक अंक कृषि क्षेत्र और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से नवाचार, सहयोग और प्रगति की कहानियाँ लेकर आता है।

आगे बढ़ते हुए, हमारा ध्यान ज्ञान साझा करने, नवीनतम विकासों को सामने लाने, क्षमता निर्माण करने और सफलता की कहानियाँ हर स्तर पर किसान के खेत से लेकर नीति-निर्माताओं तक पहुँचाने पर रहेगा। ताकि आधुनिक उपकरण, तकनीकें और सर्वोत्तम प्रथाएँ उन तक पहुँच सकें जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि यह समाचार पत्र अभी अपने प्रारंभिक चरण में है। मैं पाठकों और हितधारकों से आग्रह करता हूँ कि वे इसमें प्रस्तुत पहलों, प्रशिक्षणों और अद्यतनों से जुड़े रहें, और ऐसी प्रमुख उपलब्धियों व घटनाओं को साझा करें जिन्हें यहाँ प्रकाशित किया जा सके। इसके दायरे, प्रकाशन की आवृत्ति, नए अनुभाग जोड़ने और सुधार के लिए आपके विचार इसे एक आदर्श पत्रिका बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, जो हमें साथ मिलकर और अधिक मजबूत बनने के अवसर प्रदान करेगी।

जसवंत सिंह कालसी मुख्य परिचालन अधिकारी

हम कौन हैं:

“सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEASI)” एक स्वायत्त संस्था है, जो “एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI)” के अधीन कार्य कर रही है। यह संस्था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत किसानों, मजदूरी श्रमिकों, स्वरोजगार में लगे पेशेवरों, विस्तार कार्यकर्ताओं आदि के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण का कार्य करती है।

CEASI कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की शीर्ष संस्था है, जैसे कि:

- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर (CoE-CRA)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर (CoE-AI)

हम क्या करते हैं:

- **कौशल विकास और क्षमता निर्माण:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में हितधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर क्षमता निर्माण।
- **ज्ञान प्रबंधन:** वर्कफोर्स मानकों को समर्थन देने हेतु QPs, NOS, स्किल गैप रिपोर्ट और न्यूज़लेटर्स का विकास।
- **अनुसंधान:** उद्योग की मांगों के अनुसार आवश्यकताओं की पहचान और कौशल अंतर को पाटने के लिए अनुसंधान।
- **नीति समर्थन और परामर्श सेवाएं:** नवाचार साझा करने और क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने हेतु नेटवर्क का निर्माण।

हमारा विज़न

एक स्वायत्त उत्कृष्टता संस्थान जो कृषि में उच्च कौशल युक्त कार्यबल विकसित करने के लिए समर्पित है, नवाचार, तकनीकी प्रगति और सतत प्रथाओं के माध्यम से भारतीय कृषि की समृद्धि और लचीलापन बढ़ाने के लिए कार्यरत है।

हमारा मिशन

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उन्नत कृषि पद्धतियों में कौशल विकास के लिए अग्रणी संगठन के रूप में उभरना, जो सततता, लाभप्रदता, क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रसार, नीति समर्थन और नवाचार आधारित अनुसंधान के माध्यम से कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है।

CEASI का प्रभाव:

CEASI भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है, जो व्यक्तियों को सशक्त बनाने, कौशल को निखारने और देशभर में समुदायों को उन्नत करने का कार्य कर रहा है।

- ▶ 15+ राज्य
- ▶ 15 एफपीओ को प्रशिक्षित और सहयोग प्रदान किया गया
- ▶ 20,000 कृषि / डेयरी पेशेवरों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया
- ▶ 5000+ उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया
- ▶ 3000+ महिलाओं को सशक्त बनाया गया
- ▶ 30,000+ जीवन को प्रभावित किया गया

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय ने वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स के साथ समझौता किया



तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (TNAU) ने वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों तक आधुनिक कृषि मशीनीकरण को पहुँचाना और छात्रों को नवीनतम कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देना है। समझौते के अंतर्गत छात्रों को शोध परियोजनाओं, इंटरनशिप और आधुनिक उपकरणों पर व्यावहारिक अनुभव का अवसर मिलेगा। साथ ही, स्थानीय परिस्थितियों में कृषि मशीनरी का परीक्षण और मूल्यांकन भी किया जाएगा, जिससे किसानों को क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार समाधान उपलब्ध कराए जा सकें। समझौते पर वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स के सीईओ श्री एंटनी

चेरुकारा और टीएनएयू के रजिस्ट्रार डॉ. आर. तमिझ वेन्दन ने हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर दोनों संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों और शिक्षकों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने कहा कि यह साझेदारी छात्रों की शिक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ किसानों की उत्पादकता और लाभप्रदता बढ़ाने में भी सहायक होगी। उन्होंने बताया कि छोटे और सीमांत किसानों तक आधुनिक मशीनरी की पहुँच सुनिश्चित करने से खेती की लागत घटेगी और टिकाऊ खाद्य उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल से तमिलनाडु में कृषि क्षेत्र की क्षमता और दक्षता में वृद्धि होगी तथा किसानों को बदलती जलवायु और संसाधन संबंधी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।

कृषि और पशुपालन में तकनीक और परंपरा की भूमिका पर जोर



पुणे: ज्येष्ठ पशुवैद्य प्रतिष्ठान का 28वां स्थापना दिवस समारोह परंपरा और तकनीक के मेल पर केंद्रित रहा। विशेषज्ञों ने कहा कि भारतीय कृषि और पशुपालन में आधुनिक उपकरणों के साथ पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने से आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सकती है। कार्यक्रम में किसानों, पशुपालकों, पशु चिकित्सकों और छात्रों की उपलब्धियों को सम्मानित किया गया। छात्रों को पशु चिकित्सा विज्ञान और संबंधित विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। वक्ताओं ने कहा कि देशज नस्लों के संरक्षण और उनकी देखभाल को आधुनिक तकनीकों के साथ जोड़ना समय की आवश्यकता है। समारोह में एक स्मारिका भी जारी की गई, जिसमें संस्था की स्थापना से लेकर अब तक की उपलब्धियों का विस्तृत विवरण

दिया गया। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि पारंपरिक कृषि विधियों और आधुनिक उपकरणों के संयोजन से उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। पशु चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया गया, जिन्होंने देश की पशुधन संपदा की देखभाल में अहम योगदान दिया है। कार्यक्रम में किसानों, विशेषज्ञों और छात्रों की सक्रिय भागीदारी ने कृषि और पशुपालन में टिकाऊ विकास के लिए एक सामूहिक संकल्प को मजबूत किया।

सरकार ने कृषि मशीनीकरण से उत्पादकता बढ़ाने पर दिया जोर



भारत में 46.1% कार्यबल कृषि क्षेत्र में कार्यरत है और 2023-24 में इस क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 17.8% रहा। इस पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने कृषि मशीनीकरण को उत्पादकता बढ़ाने का मुख्य साधन माना है। 'उप-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकनाइजेशन' (SMAM) योजना के तहत किसानों को आधुनिक उपकरण और मशीनरी खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाई-टेक हब और मशीनरी बैंक स्थापित करने को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि छोटे और सीमांत किसान भी उन्नत मशीनों का लाभ उठा सकें।

सरकार की अन्य योजनाएँ भी मशीनीकरण को मजबूत कर रही हैं। 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन' (NFSNM)

किसानों को नई किस्मों के बीज, उन्नत उपकरण और जल संरक्षण यंत्र उपलब्ध करा रहा है। वहीं, 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' (PDMC) कार्यक्रम सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों जैसे ड्रिप और स्प्रींकलर को प्रोत्साहित करता है, जिससे पानी और उर्वरक की बचत होती है तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। नीतिगत स्तर पर इन पहलों का उद्देश्य कृषि को टिकाऊ, लाभकारी और तकनीक-आधारित बनाना है, ताकि किसान बदलते समय और जलवायु की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकें।

समुद्री मत्स्य पालन में तकनीक आधारित टिकाऊ कदमों की ज़रूरत



कोच्चि: आईसीएआर-सीएमएफआरआई के निदेशक ग्रीनसन जॉर्ज ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से समुद्री मत्स्य पालन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। बढ़ते समुद्री तापमान, अनियमित मौसम और आवासीय क्षति ने मत्स्य संसाधनों को चुनौती दी है। उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीकें जैसे उपग्रह निगरानी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग मछुआरों को वास्तविक समय में मछली पकड़ने के स्थानों की जानकारी दे सकती हैं। इसके अलावा, प्रवाल भित्तियों और मैंग्रोव के संरक्षण पर भी जोर दिया गया, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन से बचाव की प्राकृतिक ढाल का कार्य करते हैं।

ग्रीनसन जॉर्ज ने कहा कि तकनीक-आधारित समाधान तभी प्रभावी होंगे जब मछुआरों और स्थानीय समुदायों की

भागीदारी सुनिश्चित हो। उन्होंने साझेदारी और ज्ञान-साझाकरण मंचों को मजबूत बनाने की आवश्यकता बताई। हाल ही में कोच्चि में आयोजित एक संगोष्ठी में वैज्ञानिकों ने भी चिंता जताई कि बदलती जलवायु के कारण समुद्री प्रजातियों का वितरण और पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े बदलाव हो रहे हैं। विशेषज्ञों का मत था कि विज्ञान, तकनीक और समुदाय की साझेदारी ही समुद्री मत्स्य पालन को टिकाऊ बनाएगी और तटीय क्षेत्रों की आजीविका को सुरक्षित रखेगी।

दक्षिण गारो हिल्स के 250 से अधिक किसानों को आईसीएआर-आईआईएचआर बागवानी तकनीकों का लाभ



दक्षिण गारो हिल्स के 250 से अधिक किसानों को बागवानी फसल उत्पादन को सशक्त बनाने हेतु आईसीएआर-आईआईएचआर की उन्नत तकनीकों पर आधारित क्षमता निर्माण कार्यक्रम से लाभ मिला। यह कार्यक्रम छोटो बोलांग्रे, पुराखासिया में आयोजित किया गया, जिसका संयुक्त आयोजन नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (एनईएचयू) तुरा परिसर के उद्यानिकी विभाग और ऑल गारो हिल्स मल्टीपरपज़ कोऑपरेटिव सोसायटी (एजीएचएमपीसीएस) द्वारा किया गया। किसानों को भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईआईएचआर), बेंगलुरु द्वारा विकसित "अर्का" सब्जी बीज किट प्रदान की गई तथा उत्पादन बढ़ाने, आय सुधारने और क्षेत्र को बागवानी निर्यात केंद्र के रूप में विकसित

करने हेतु आधुनिक तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यक्रम में आधुनिक तकनीकों की भूमिका पर जोर दिया गया, जिससे किसान उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर उन्मुख होकर आर्थिक अवसरों का लाभ उठा सकें। आयोजकों ने उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की सतत आपूर्ति, तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को निरंतर सहायता का आश्वासन दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला किसानों की भागीदारी उल्लेखनीय रही, जो मेघालय में सतत आजीविका विकास के लिए नवाचारपूर्ण तरीकों को अपनाने की बढ़ती सामुदायिक भागीदारी को दर्शाती है।

परागण व फसल उत्पादन हेतु मधुमक्खियों के संरक्षण पर जोर



मुदिगेरे में कॉफी उत्पादकों से मधुमक्खियों के संरक्षण को प्राथमिकता देने का आह्वान किया गया, ताकि पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित रहे और फसल उत्पादन में वृद्धि हो। यह संदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) में आयोजित मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान दिया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि मधुमक्खियों की संख्या में गिरावट पारिस्थितिक संतुलन के लिए गंभीर खतरा है। किसानों से अपील की गई कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएँ, जिनके अंतर्गत अनुदान पर मधुमक्खी के छत्ते और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सतत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा सके।

तकनीकी सत्रों में बताया गया कि मधुमक्खी पालन एक

लाभकारी उद्यम है जिसकी बाजार में उच्च मांग है। वैज्ञानिक तरीकों और उचित देखभाल अपनाकर किसान उत्पादन बढ़ा सकते हैं, अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं और कॉफी जैसी फसलों में परागण को मजबूत बना सकते हैं। अधिकारियों ने जोर दिया कि मधुमक्खियाँ फसल उत्पादकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं और उद्यानिकी व कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रमों और तकनीकी मार्गदर्शन के माध्यम से निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

प्रयागराज के किसान ड्रैगन फ्रूट की सुरक्षा हेतु बैगिंग तकनीक अपनाते हुए



प्रयागराज एवं आसपास के क्षेत्रों के किसान बरसात के मौसम में ड्रैगन फ्रूट की फसलों की सुरक्षा के लिए तेजी से फल बैगिंग तकनीक अपना रहे हैं। इस पद्धति में प्रत्येक फल को कागज़ या कपड़े के थैलों से ढक दिया जाता है, जिससे एक सूक्ष्म वातावरण तैयार होता है जो फलों को कीटों, रोगों और बारिश से होने वाले नुकसान से बचाता है। यह तरीका न केवल फलों की गुणवत्ता और स्वरूप को बेहतर बनाता है, बल्कि अत्यधिक वर्षा और फफूंद से होने वाले नुकसान को भी कम करता है। राज्य सरकार एकीकृत उद्यानिकी मिशन के अंतर्गत किसानों को आर्थिक सहायता और अनुदान प्रदान कर इस सतत पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

अधिकारियों ने बताया कि बैगिंग तकनीक सुरक्षित फसल और अधिक पैदावार सुनिश्चित करने का प्रभावी उपाय साबित हुई

है। कई किसानों ने विपरीत मौसम परिस्थितियों के बावजूद बेहतर आय की सूचना दी है। इसकी सफलता से प्रेरित होकर आस-पास के जिलों के कृषक भी ड्रैगन फ्रूट की खेती और बैगिंग तकनीक अपनाने लगे हैं। गैर-पारंपरिक उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देकर यह क्षेत्र किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि देख रहा है, जो सतत बागवानी विकास की दिशा में सकारात्मक कदम है।

हरियाणा में मधुमक्खी पालकों को सहारा, भावांतर भरपाई योजना में शामिल हुआ शहद



किसानों और मधुमक्खी पालकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में शहद को अब भावांतर भरपाई योजना (बीबीवाई) में शामिल किया गया है, जिससे उन्हें बागवानी फसलों की तर्ज पर उचित मूल्य सुनिश्चित हो सकेगा। रामनगर में आयोजित राज्यस्तरीय मधुमक्खी पालन कार्यशाला में बताया गया कि शीघ्र ही एक शहद बिक्री एवं भंडारण केंद्र गुणवत्ता परीक्षण सुविधाओं के साथ एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र (आईबीडीसी) में स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ₹20 करोड़ की लागत से एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला भी बनाई जा रही है तथा रामनगर केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का उन्नत शोध और प्रशिक्षण संस्थान विकसित किया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि मधुमक्खी पालन न केवल किसानों

को अतिरिक्त आय का स्रोत प्रदान करता है बल्कि परागण के माध्यम से फसल उत्पादन भी बढ़ाता है। मधुमक्खी पालन नीति-2021 के अंतर्गत राज्य ने हजारों मधुमक्खी पालक तैयार करने और वर्ष 2030 तक शहद उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। किसानों को मधुमक्खी बक्सों, कालोनियों और उपकरणों पर 85% तक अनुदान, साथ ही प्रशिक्षण और प्रसंस्करण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य सरकार इसे एक लाभकारी, सतत और युवाओं के लिए उपयुक्त उद्यम के रूप में बढ़ावा दे रही है।

बनास डेयरी ने उत्पादकों और समितियों को ₹2,909 करोड़ भुगतान की घोषणा की



एशिया की सबसे बड़ी सहकारी दुग्ध संघ, बनास डेयरी ने अपनी 57वीं वार्षिक आम सभा (AGM) के दौरान ₹2,909.8 करोड़ के रिकॉर्ड वितरण की घोषणा की है। इसमें से ₹2,131 करोड़ सीधे पंजीकृत दुग्ध उत्पादकों को क्रय मूल्य के रूप में दिए जाएंगे, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18.32% की वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त ₹778.12 करोड़ दुग्ध सहकारी समितियों को वितरित किए जाएंगे।

अध्यक्ष शंकर चौधरी ने बताया कि दुग्ध क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सहकारी संस्था बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। साणदर में 150 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता वाला एक नया मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसे भारत का सबसे बड़ा प्लांट माना जा रहा है। इसके अलावा, बनास बोवाइन ब्रीडिंग एंड रिसर्च सेंटर (BBBRC) भी भिलाड़ी

में स्थापित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पशु प्रजनन और अनुसंधान को बढ़ावा देना है।

वित्तीय प्रगति पर प्रकाश डालते हुए चौधरी ने कहा कि डेयरी का ऋण दायित्व ₹2,000 करोड़ से घटकर ₹610 करोड़ रह गया है, जिसमें से ₹1,389 करोड़ का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। क्रय मूल्य और वार्षिक बोनस सहित सभी भुगतान सीधे उत्पादकों के बैंक खातों में जमा किए जाते हैं।

एनडीआरआई ने साहिवाल गायों के लिए भारत का पहला जीनोमिक चयन कार्यक्रम शुरू किया



करनाल स्थित आईसीएआर-राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एनडीआरआई) ने साहिवाल गायों के लिए भारत का पहला जीनोमिक चयन कार्यक्रम शुरू किया है। यह पहल आनुवंशिक सुधार को तेज करने, दूध उत्पादन बढ़ाने और छोटे व मध्यम डेयरी किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

कार्यक्रम की घोषणा करते हुए एनडीआरआई के निदेशक डॉ. धीर सिंह ने कहा कि जीनोमिक चयन पारंपरिक प्रजनन की तुलना में तेज परिणाम देगा। "जहां पारंपरिक फेनोटाइप-आधारित तरीके 7-8 वर्ष लेते हैं, वहीं जीनोमिक्स कुछ ही हफ्तों में श्रेष्ठ सांडों की पहचान कर सकता है। इससे जीनोमिक रूप से परीक्षण किए गए साहिवाल सांडों का उच्च

गुणवत्ता वाला वीर्य किसानों तक शीघ्र पहुँचेगा, जिससे पशुधन की उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ेगी," उन्होंने बताया। यह कार्यक्रम भारतीय परिस्थितियों के अनुसार विकसित उन्नत जीनोमिक मॉडलों पर आधारित है, जो छोटे किसानों, बहु-नस्ल झुंडों और सीमित वंशावली रिकॉर्ड वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं। डॉ. विकास वोहरा के नेतृत्व में डॉ. अनुपमा मुखर्जी, डॉ. रानी एलेक्स, डॉ. गोपाल गोवाने और डॉ. टी.वी. राजा की टीम ने साहिवाल गायों पर व्यापक परीक्षण कर जीनोमिक प्रजनन मूल्य (GBV) विकसित किए हैं।

यह महत्वपूर्ण उपलब्धि राज्य और केंद्र की नस्ल सुधार योजनाओं को सशक्त बनाएगी तथा पूरे देश में उच्च गुणवत्ता वाली आनुवंशिकी तक किसानों की पहुँच को बढ़ाएगी।

पशु कृषि के भविष्य पर सीएलएफएमए की 58वीं वार्षिक आम बैठक और 66वां राष्ट्रीय संगोष्ठी 2025 का आयोजन



हैदराबाद में 22-23 अगस्त 2025 को कंपाउंड लाइवस्टॉक फीड मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CLFMA) की 58वीं वार्षिक आम बैठक और 66वां राष्ट्रीय संगोष्ठी ताज डेक्कन, बंजारा हिल्स में आयोजित होगी। "एनिमल एग्रीकल्चर इन इंडिया – द वे फॉरवर्ड" थीम पर आधारित इस दो दिवसीय कार्यक्रम में नीति-निर्माता, उद्योग जगत के नेता और विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो पशुपालन, डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य क्षेत्र के भविष्य पर चर्चा करेंगे।

उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता प्रो. एस. पी. सिंह बघेल, भारत सरकार के मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी और पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री करेंगे, जिनके साथ तेलंगाना के वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

सीएलएफएमए के चेयरमैन दिव्य कुमार गुलाटी ने भारत के पशुधन क्षेत्र को ग्रामीण समृद्धि का आधार बताते हुए निर्यात-उन्मुख क्षेत्र (Export Oriented Zones) और लाइवस्टॉक एक्सपोर्ट एवं डोमेस्टिक डेवलपमेंट अथॉरिटी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिल सके।

कार्यक्रम में मुख्य भाषण, पैनल चर्चाएँ और थीमैटिक सत्र होंगे, जिनमें प्रतिस्पर्धा, नवाचार, स्थिरता और भारत को पशु कृषि में वैश्विक नेता बनाने की रणनीतियों पर विचार किया जाएगा।

पंजाब में डेयरी जेनेटिक्स और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए वेट वर्सिटी और पीडीएफए ने किया समझौता



लुधियाना स्थित गुरु अंगद देव वेटेरिनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी (GADVASU) ने प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन (PDFA) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य पंजाब में आनुवंशिक सुधार और दूध उत्पादन को सुदृढ़ करना है।

समझौते के तहत, पीडीएफए सदस्यों की गायों से चुने गए उत्कृष्ट होल्सटीन फ्रीजियन (HF) और जर्सी नस्ल के बछड़ों का प्रजनन हेतु उपयोग किया जाएगा। विश्वविद्यालय इन बछड़ों से उच्च गुणवत्ता वाले जमे हुए वीर्य खुराक (Frozen Semen Doses) तैयार करेगा और उन्हें पीडीएफए के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराएगा। इससे किसानों को श्रेष्ठ जर्मप्लाज्म तक व्यापक पहुँच मिलेगी और स्थायी आनुवंशिक

सुधार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, बैलों की संतति परीक्षण (Progeny Testing) के लिए सटीक डेटा भी तैयार होगा।

कुलपति डॉ. जे.पी.एस. गिल ने कहा कि यह पहल पशुधन की आनुवंशिक गुणवत्ता को बढ़ाएगी, दूध उत्पादन में सुधार करेगी और एक स्थायी विकास मॉडल स्थापित करेगी। पीडीएफए अध्यक्ष सरदार दलजीत सिंह गिल ने बताया कि पंजाब में उच्च गुणवत्ता वाले HF और जर्सी वीर्य की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन आपूर्ति अनियमित और महंगी है।

अधिकारियों ने बताया कि पंजाब पहले ही उत्कृष्ट HF और जर्सी जर्मप्लाज्म का केंद्र बन चुका है और यह सहयोग राज्य की भूमिका को भारत के डेयरी क्षेत्र में और मजबूत करेगा।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर कृषि में स्पेस टेक्नोलॉजी की भूमिका



नई दिल्ली: राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर आईसीएआर, पूसा में आयोजित कार्यक्रम को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान ने भारतीय कृषि में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। इसरो के 'जियो पोर्टल' से किसानों को वर्षा, सूखा, मिट्टी की नमी और फसल स्वास्थ्य की सटीक जानकारी मिलती है। इससे किसान खेती की बेहतर योजना बना पा रहे हैं। चौहान ने बताया कि अब उपग्रह आधारित तकनीक से फसल हानि का सही आकलन संभव है, जिससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पारदर्शिता बढ़ी है।

मंत्री ने कहा कि अब कीट पहचान और गेहूं की बुवाई व कटाई की वास्तविक समय में निगरानी भी संभव हो गई है। उन्होंने वैज्ञानिकों से नकली खाद-कीटनाशक की पहचान करने वाले उपकरण विकसित करने और दलहनों-तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने पर काम करने का आग्रह किया। चौहान ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि पर बधाई दी और चंद्रयान की सफलता को देश की वैज्ञानिक क्षमता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों की प्रतिभा और प्रयास कृषि को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और छोटे किसानों तक तकनीक का लाभ पहुँचाना ही सरकार की प्राथमिकता है।

अरुणाचल विश्वविद्यालय के कृषि छात्रों ने सीखा जलवायु अनुकूल तकनीक



20 अगस्त 2025, नामसाई: अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ के 25 कृषि छात्र और अध्यापक आईसीएआर-कृषि विज्ञान केंद्र (KVVK), नामसाई पहुँचे। यहां उन्हें जलवायु अनुकूल तकनीकों और उनके व्यावहारिक उपयोग की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बताया गया कि जलवायु परिवर्तन कृषि के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर रहा है और इस चुनौती से निपटने के लिए विज्ञान केंद्र किसानों तक नई तकनीकें पहुँचा रहे हैं। छात्रों ने धान की डूब-सहनशील किस्म 'रंजीत सब-1', अल्प-अवधि वाली किस्म 'डिसांग', सूखा-सहनशील तोरिया 'टीएस-38' और समेकित खेती प्रणाली देखी, जिसमें फसल, पशुपालन, मत्स्य और डकरी शामिल हैं।

इसके अलावा, छात्रों को मशरूम उत्पादन, वर्मी कम्पोस्टिंग, मधुमक्खी पालन जैसी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें 'लीफ कलर चार्ट' के उपयोग से नाइट्रोजन प्रबंधन करने की विधि बताई गई, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम किया जा सकता है। कार्यक्रम में 'पार्थेनियम जागरूकता सप्ताह' और 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण गतिविधियाँ भी हुईं। अंत में छात्रों ने प्रदर्शन खेत का भ्रमण किया और वैज्ञानिकों से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाया। इस पहल से छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान के साथ-साथ टिकाऊ कृषि की दिशा में नई प्रेरणा मिली।

शाश्वत मिठास पहल के अंतर्गत अयोध्या में जलवायु-स्मार्ट गन्ना खेती को सशक्त बनाना

शाश्वत मिठास पहल के अंतर्गत, सेंटर ऑफ एक्सीलेस फॉर एग्रीकल्चर स्कलिस इन इंडिया (CEASI) ने UPL SAS लिमिटेड के सहयोग से अयोध्या में सतत गन्ना खेती की प्रथाओं को सशक्त बनाने की दृष्टि में कार्य किया है। अब तक 500 किसानों का सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें 89 असंगठित और 3 संगठित किसान समूह शामिल हैं, ताकि वर्तमान खेती की पद्धतियों का आकलन किया जा सके और सुधार के अवसरों की पहचान हो सके। इन जानकारीयों के आधार पर, ग्राम स्तर पर प्रदर्शन प्लॉट स्थापित किए गए हैं, जिनमें जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और जैविक इनपुट के उपयोग जैसी सर्वोत्तम प्रथाएँ प्रदर्शित की जाती हैं।

सामुदायिक भागीदारी और किसान-से-किसान सीखने को बढ़ावा देने के लिए, इस पहल के अंतर्गत 89 खुदरा विक्रेताओं के साथ संवाद, 8 फील्ड डे का

आयोजन और 500 एक-से-एक किसान संपर्क गतिविधियों की गई है। इन मंचों पर किसान सीधे विशेषज्ञों से बातचीत करते हैं, अपनी जमीनी चुनौतियाँ साझा करते हैं और जलवायु-लचीली तकनीकों को व्यवहार में अपनाते हुए देखते हैं।

मैदान अनुसंधान, व्यावहारिक प्रदर्शनों और सक्रिय हतिधारक भागीदारी के माध्यम से, यह पहल गन्ना उत्पादकों को पर्यावरण-अनुकूल, संसाधन-दक्ष तकनीकों से सशक्त करती है, जो उपज बढ़ाने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन विकसित करने में सहायक है। इसका व्यापक लक्ष्य केवल गन्ने की उत्पादकता बढ़ाना ही नहीं, बल्कि अयोध्या क्षेत्र में पारिस्थितिकीय स्थिरता और समावेशी कृषि विकास के लिए एक दोहराने योग्य मॉडल स्थापित करना भी है।





CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA



(CEASI), Unit No. 101, First Floor, Greenwoods
Plaza, Block 'B' Greenwoods City, Sector-45,
Gurugram, Haryana-122009



+91 74287 06078



info@cedsi.in



www.ceasi.in



@ceasi_india